कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ – 1 / 822 / 2021 / 10 – 11 / **12** G

भोपाल, दिनांक 12/01/2022

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003

विषय:—वन मंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा के कक्ष क्र. PF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि बण्डर आयमण्ड ओपन कास्ट पद्धित से हीरा उत्खनन हेतु मेसर्स एस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 22/11/2021

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 22/11/2021 से वन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 12.07.2016 में की गई अनुशंसाओं पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25/10/2021 से प्रस्तुत उत्तर पूर्ण उत्तर नहीं होने से भारत सरकार के पत्र दिनांक 18/10/2021 पर पुनः वन विभाग का अभिमत चाहा गया है जो निम्नानुसार है:—

 As per NTCA report, project can potentially disrupt the landscape character vis a vis tiger dispersal around panna landscape as such this may be taken only when ken Betwa link project is finalized as well as detailed study done to assess other alternatives.

रियो टिंटों कम्पनी द्वारा जब पूर्व में इस खदान के लिये आवेदन किया था तब केन बेतवा परियोजना स्वीकृत नहीं हुई थी। केन बेतवा परियोजना में 6017 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक अनुमति भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2017 से जारी की गई है।

केन बेतवा परियोजना में भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त क्रमांक—23 (iii) के अनुसार इस लेण्डस्केप की प्रबंध योजना एन.टी.सी.ए. तथा वन्यप्राणी संस्थान देहरादून के द्वारा तैयार की जाना है तथा इस प्रबंध योजना को आवेदक संस्था के व्यय पर लागू किया जाना है। केन बेतवा परियोजना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक अनुमित की शर्तों के अनुसार कार्यवाही आवेदक संस्था द्वारा की जा रही है।

382.131 हेक्टेयर के इस प्रस्ताव में सिम्मिलित वनक्षेत्र के संबंध में पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि यह वनक्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का भाग नहीं है और न ही किसी कॉरीडोर का हिस्सा है। मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा दिनांक 02.12.2019 को जारी प्रेसनोट में एन.टी.सी.ए. एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से Connecting Tiger Populations for Long-grem Conservation विषय पर देश में स्थापित कॉरीडोर की जो सूची प्रकाशित की है, उसमें प्रस्तावित वनक्षेत्र सम्मिलित नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा विकसित DSS प्रणाली तथा एन.टी.सी.ए. एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान से करवाई जा सकती है।

इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि रियोटिंटो द्वारा पूर्व में जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तब प्रभावित वनक्षेत्र के निकटवर्ती वनक्षेत्रों में वन्यप्राणी प्रबंधन के लिये वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। रू. 30.80 करोड़ की इस प्रबंधन योजना की स्वीकृति मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 11.02.2016 से जारी की गई है। इस स्वीकृत योजना के अनुसार आवेदक संस्था से राशि प्राप्त कर प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन का कार्य किया जायेगा।

 User agency has submitted the revised proposal which is highly dependent on suface extraction which would entail greater extent of forest land use leading to permanent loss of the high quality foerst areas.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था को पत्र दिनांक 07.12.2021 से लेख करते हुये अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिये लेख किया गया था। आवेदक संस्था ने पत्र दिनांक 08.01.2022 से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इस परियोजना में चाही गई भूमि न्यूनतम है। इस परियोजना में प्रभावित होने वाले लगभग 2 लाख वृक्षों के विरुद्ध आवेदक संस्था द्वारा आगामी वर्षों में 8 लाख पौधें रोपित किये जायेगे। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी विभागीय रूप से प्रभावित वनक्षेत्र के आस-पास के वनों में आगामी वर्षों में 10 लाख पौधें रोपित करने के निर्देश दिये है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में उल्लेखित 382.131 हेक्टेयर में से 112 हेक्टेयर वनक्षेत्र में एक तालाब निर्मित किया जावेगा, जिसका कालांतर में प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रभावित 2 लाख वृक्ष कार्य प्रारम्भ होने के बाद धीरे-धीरे 10 से 12 वर्ष में काटे जायेंगे। आवेदक संस्था द्वारा रिक्लेमेंशन योजना के अनुसार रिक्लेमड क्षेत्र में रोपण भी साथ-साथ कर दिया जायेगा।

The Project proponent may also explore the possibility of underground.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि यह कार्य अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग के माध्यम से किया जाना सम्भव नहीं है। यदि यह कार्य अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग के माध्यम से किया जाता है तो काफी मात्रा में मिनरल्स को निकाल पाना सम्भव नहीं होगा। अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग के माध्यम से दोहन कार्य व्यवहारिक न होने का कारण आवेदक संस्था ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2022 में विस्तार पूर्वक दिया है।

आवेदक संस्था के द्वारा दिया गया प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2022 क्री प्रति संलग्न है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-1 / 822 / 2021 / 10-11 / [27 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक [2 01 2022

- वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, छतरपुर मध्य प्रदेश।
- मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला ग्रुप एस.के. अहीर मार्ग, मुम्बई (महाराष्ट्र)

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल





EMIL/Bunder/HO/2022/02

8 January 2022

The PCCF (Land Management) & Nodal Officer Forest Department, Government of Madhya Pradesh Satpuda Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh

Subject: Proposal of Forest diversion of 382.131 Ha of forest land for Bunder Diamond Mining Project in favour of M/s Essel Mining & Industries Limited, District Chhatarpur, State of Madhya Pradesh (Online Proposal No: FP/MP/MIN/45288/2020) – regarding

Reference: 1) Letter from your office bearing no F-1/822/2021/10-11/4070 dated 7 Dec 2021
2) EDS from MoEF&CC, New Delhi bearing no FC-8-04/2021-FC dated 22 Nov 2021

Dear Sir,

With reference to your letter number F-1/822/2021/10-11/4070 dated 7 Dec 2021, seeking response to the EDS queries sought by MoEF&CC, New Delhi vide its letter number FC-8-04/2021-FC dated 22 Nov 2021, we wish to submit as under;-

Project Background

Bunder Diamond is one of the most important and significant discoveries in last 25 years across the globe, and the first diamond discovery in India for over 40 years. It is one of the few advanced stage project in last 15 years likely to become functional globally in immediate future. Finding economic diamond deposit is difficult, over the last 140 years, almost 7000 kimberlite pipes have been sampled by geologists, about 1000 of which have been diamondiferous. However only about 60 were sufficiently rich in diamonds to be economically viable (0.86% only) & just 7 could be referred as "Tier 1" deposit with more than US\$20 Billion worth of reserves (0.1%) or 1 in 1000.

The Bunder Diamond Block is allocated to Essel Mining & Industries (EMIL) as auctioned mine under the provisions of MMDR Amendment Act 2015 and Mineral Auction Rule 2015.

 The Directorate of Geology & Mining, Government of Madhya Pradesh (GoMP) on 5 Jul 2019 have issued Notice Inviting Tender (NIT) for grant of Mining Lease through auction over an area of 364 Ha in Bunder Diamond Block.

Essel Mining & Industries Ltd.



- EMIL have participated in the auction process and submitted the highest bid of revenue share
 of 30.05% in the competitive auction process. In addition to this revenue share EMIL shall
 also pay 12.88% as Royalty, DMF & NMET and applicable taxes to the government
 exchequer.
- The project will contribute about INR 28,000 Crores to the exchequer based on the value of
 estimated resources. The project shall create employment for locals in the range of 1000 to
 1500 (direct + indirect) and contribute in big way for socio economic development of
 industrially deprived district of Chhatarpur.
- EMIL was declared as Preferred Bidder after depositing Rs 27.52 Crores towards first tranche of upfront payment as mandated under the provisions of MMDR Amendment Act 2015 and Mineral Auction Rules 2015 and thereafter LOI for grant of Mining lease was issued on 19 Dec 2019.
- The LoI mandates EMIL to obtain all statutory clearances required for grant of Mining lease within 3 years from grant of LoI which can be extended by 2 years. EMIL is currently in the process of obtaining statutory clearance including forest clearance under the provisions of Section 2 of the Forest Act 1980.

Point 1: Response to disruption of landscape etc.

- The Forest department of Madhya Pradesh vide letter No F-1/822/2021/10-11/577 dated 5 February 2021 to MOEF&CC, New Delhi (enclosed as Annexure 1) have confirmed the following:-
 - The location of forest diversion area of Bunder Diamond Block is located at distance of,
 - √ 19.03 Km from the Buffer zone of Panna Tiger Reserves.
 - √ 41 Km from the Biosphere reserve & Core Zone of Panna Tiger Reserves.
 - √ 90 Km from the Ken Ghariyal Wildlife Sanctuary.
 - o The forest diversion area in Bunder Diamond Block,
 - √ do not form part of any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc.
 - ✓ is not located within eco-sensitive zone (ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife (Protection) Act, 1972.
 - ✓ is not located within 10 Kms area any Protected area or Eco Sensitive Zone.
- The DDG, Forest, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Central Zone, Bhopal during site
 inspection on 30 June 2021 have vetted and validated the above facts and the same have been
 mentioned in the Site inspection report dated 2 July 2021 (Kindly refer page no 2). The copy of Site
 Inspection report is enclosed as Annexure 2.
- The Chief Wildlife Warden, Bhopal, Madhya Pradesh vide letter VaPra/Ma Chi/Rio Tinto/Mines/13-3/1368 dated 11 February 2016 has approved the Wildlife Conservation Plan

Essel Mining & Industries Ltd.



for Rio Tinto over an area of 971.595 Ha. The 364 Ha Mining lease area granted to EMIL is subset of 971.595 Ha over which the Wildlife Conservation Plan is already approved. If directed the Project Proponent may implement the said approved Wildlife Conservation plan. Copy of the approval is enclosed as Annexure 3.

- The State Government of MP vide letter dated 28 Jan 2021 has confirmed that the proposed Bunder
 Diamond project is outside of Conservation area, Buffer Zone and Eco sensitive zone and therefore
 Wildlife Clearance is not applicable. The copy of letter from State Government is enclosed in
 Annexure 4.
- The proposed Bunder Diamond Block do not form part of any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. the same is verified from the Decision Support System developed by Forest Survey of India, Dehradun.
- The forest diversion area do not form part of any tiger reserves nor any tiger corridor, copy of the
 existing tiger corridor published in the report titled "Connecting Tiger Population for Long term
 Conservation" prepared by National Tiger Conservation Authority is enclosed in Annexure 5.
- The approval for Ken Betwa project has been accorded by Union Cabinet, Government of India on 8 Dec 2021.

Point 2: Response to loss of forest

- Utmost care have been taken to minimize the impact on the forest, the Reconnaissance work started over an area of 2450 Sq. Km in Chhatarpur, Sagar, Tikamgarh & Damoh culminating to identification of Prospecting License of 70 Sq. Km which got converted into mining lease of 9.54 Sq. Km (954 Ha).
- In order to further reduce the footprint, the Government of Madhya Pradesh have drastically reduced the mining lease area by more than 60% from 954 Ha (proposed to Rio Tinto) to 364 Ha while auctioning the block under the new legislative regime of MMDR Amendment Act 2015 and Mineral Auction Rule 2015.
- The area requested by the present project proponent (EMIL) for diversion under the Forest Act 1980 is 382.131 Ha only and is about 39% of 971.595 Ha applied by the erstwhile lessee Rio Tinto.
- The number of trees getting impacted by the forest diversion proposal submitted by Rio Tinto was "694689" while the present proposal submitted by EMIL involves merely "215875" trees which is 72% less than the previous application. It is important to mention that the above number of trees will be impacted over a period of 10 12 years, whereas the plantation is proposed much ahead of tree felling ensuring the total forest is compensated / developed / grown in advance.
- The Project Proponent shall take all necessary measures to optimize the number of trees under impact and have already confirmed in response to the letter no FC-8-04/2021-DC dated 1 July 2021 of MoEF&CC, New Delhi that, EMIL will optimize the number of trees by 15000-16000 trees

Essel Mining & Industries Ltd.



thereby reducing the total trees under impact to less than 2 Lacs. The copy of the previous response is enclosed as **Annexure 6**.

- In order to compensate loss of forest a Compensatory Afforestation (CA) Scheme is prepared by DFO, Chhatarpur and approved by CCF. The scheme warrants planting "383000" trees thus compensating about 1.8 times of the trees proposed for diversions. The plantation will be undertaken in the same forest division which shall help to restore the ecology of the local area. To further state that deforestation activity will be phased over a period of 10 -12 years.
- The Mine Plan approved by Indian Bureau of Mines mandates EMIL to plant another "425000" trees within the mine lease area as part of reclamation and rehabilitation. The reference for the approved mine plan is enclosed as reference in Annexure 7.
- The aforementioned plantation of "425,000" trees within mining lease area as part of reclamation
 plan is also reported in the Site Inspection Report by DDG Forest, Regional Office, MoEF&CC,
 Bhopal (Kindly refer page 7), the Site Inspection Report is enclosed as Annexure 2.
- Thus the Project Proponent shall plant 808000 trees which is 400% or 4 times of 200000 trees likely to be impacted.
- As per the approved mine plan the project proponent will progressively rehabilitate and restore the project area by undertaking progressive plantation within the mine lease area. At the end of mine life, the complete ML area will be rehabilitated, restored and handed over back to the Forest department. Apart of planting 425,000 trees within mining lease area about 112 Ha area will be developed as water body to promote aquatic life and support migratory birds thus adding to the diversity of wildlife in the area. This large waterbody will also improve ground water recharge and serve as a water hole for wild animals in the surrounding area particularly in the dry summer months.
- The Hon'ble Chief Minister of MP in the development project review meeting on 7 June 2021 has directed that within state wherever deforestation activities are proposed for project development there we should plant multiple time of deforested trees so that there is no harm to environment. He further stated that in Chhatarpur district where one development project is proposed may lead to deforestation of 2 Lacs trees should be backed by afforestation of 10 Lacs trees. The Hon'ble Chief Minister of MP emphasized that CAMPA fund can be used for additional plantation, maintenance of forest etc.
- The Bunder Diamond project will be one of the largest efforts in India to compensate phased loss of about 2,00,000 trees with planting in over 18,00,000 trees, thus compensating not only in terms of numbers but also the loss of Ecosystem services.
- · The project is also mandated to pay prescribed NPV that will compensate the loss of forest.
- Proposed 364 hectares of forest land is much lesser than the area proposed to the erstwhile lessee
 Rio Tinto and comprises of about 0.25% of the total forest cover of Chattarpur, in other words only
 1 tree in every 400 trees will be impacted.

Essel Mining & Industries Ltd.

Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.

T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.
Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728



The forest diversion proposal forwarded by the State Government to MoEF&CC, New Delhi
has been vetted, validated and recommended by the DDG, Forest of Integrated Regional
Office, MoEF&CC, Central Zone, Bhopal.

Point 3: Response to explore options of Underground Mining

Natural diamonds are formed under high pressure and temperature at depths extending few hundred Kms in the Earth's mantle. Diamond or carbon crystals so formed are carried to the surface through volcanic eruptions and deposited in igneous rocks known as kimberlites or Lamporite, its because of the geometrical shape these type of orebodies are called pipes. The morphology of kimberlite pipes (or eruption) and their classical carrot shape / Inverted cone is the result of explosive diatreme volcanism from very deep mantle-derived sources. Schematic of Kimberlite Pipe is provided in Figure 1

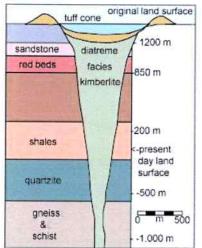


Figure 1: Schematic of Kimberlite Pipe

The proposed lease area in Bunder Diamond Block contains only one Kimberlite pipe known as Atri Pipe which is exposed right upto the surface and is amicable to surface / opencast mining only.

Directorate of Geology & Mining, Government of Madhya Pradesh in compliance to Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015) have prepared the Geological report for Bunder Diamond Block. The Geological report provides mineral reserves of 53.7 Mt of Kimberlite at incidence rate of 0.63 Carat/ton upto depth of 350 meters from the surface in the block. The Bunder Diamond block is amenable to opencast method of mining and therefore the government have reported the reserves & mining type based on adopting opencast mining. Relevant extracts of Geological report published along with Tender of Bunder Diamond Block is enclosed as **Annexure 8**.

Essel Mining & Industries Ltd.





It is important to mention that the Bunder Diamond Block forms the part of Vindhyan Sedimentary Basin. The Kimberlites pipes is exposed right upto the surface and is divided in two domains namely North Atri and South Atri.

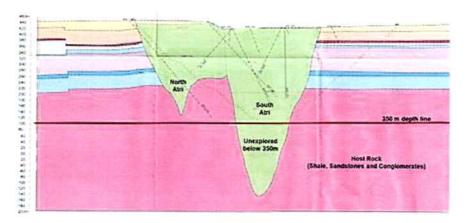


Figure II: Longitudinal Section of Ore Body (Source: IBM Approved Mine Plan)

The Atri pipe in the proposed mining lease area being conical in shape thus contains higher tonnages (more than 55% of total tonnages) in upper sections which reduces with depth. Importantly diamond incidence is also higher near surface and reduces in the deeper sections of ore body.

- a) Adoption of underground mining in the present case will block major volumes and quantity as part of Crown Pillar required for supporting underground mine workings and surface structures reducing the available tonnages drastically from the auctioned mineral resource base of 53.7 Million Tonnes. It will further reduce the scale of operations.
- b) The underground mining methods provides limited extractability of the ore and in the best case it enables extraction in the range of 70 75 % of the available ore.
- c) Underground mining projects have long gestation period.

Thus in the event underground mining is adopted majority of ore will be blocked as pillar (not available for mining), the available tonnage will reduce the scale of operation drastically, followed by long gestation period which will seriously impact the techno commercial viability of the project making it unviable.

Essel Mining & Industries Ltd.

Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.
T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.
Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728





Adoption of underground mining methods in the case Bunder Diamond project will not only be an unviable proposition but will also compromise the principles of mineral conservation and optimum extractions of mineral resources be compromised. It is paramount importance to mention that the Govt of Madhya Pradesh have already reduced the mining lease area by more than 62% considering minimal footprint, scientific extraction of the mineral resource kimberlite in this case.

Submitted for your kind perusal and look forward for your earliest action in this regard for propelling the proposal forward.

Thanking you

For Essel Mining & Industries Limited



President and Project Head - Bunder Diamond Block

Enclosed

- 1. Annexure 1: The State Government letter No F-1/822/2021/10-11/577 of 5 Feb 2021
- 2. Annexure 2: Site Inspection Report by DDG Forest, MoEF&CC, Bhopal
- 3. Annexure 3: Wildlife Clearance granted to Rio Tinto
- 4. Annexure 4: State Government letter dated 28 Jan 2021
- 5. Annexure 5: Press Note on Tiger Corridor published by NTCA
- 6. Annexure 6: Response to letter no FC-8-04/2021-DC dated 1 July 2021
- 7. Annexure 7: Extracts from Approved Mine Plan
- 8. Annexure 8: Extracts from Geological report of Bunder Diamond Block

68

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमाक एफ-1/822/2021/10-11/577 मोपाल, दिनांक 05/02/2021

प्रति.

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003

विषय:- वन मंडल छत्तरपुर के परिक्षेत्र वकरवाहा के वन कक्ष RF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकवा 382.131 है. वनभूमि में बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धित से हीरा उत्खनन का मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का प्रस्ताव FP/MP/MIN/45288/2020/

--0--

मुख्य वन संरक्षक, छत्तरपुर के पत्र दिनांक 02/01/2021 से विषयान्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- मेसर्स ऐरसैल गाईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड. मुम्बई को खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क. एफ-3-26/2019/12/1 दिनांक 19/12/2020 से रकवा 364.000 हेक्टेयर वन भूमि में वण्डर डायमण्ड परियोजना हेतु माईनिंग लीज की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 2. मेसर्स ऐरसेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य विडला ग्रुप, एस.कं. अहीर मार्ग, मुम्बई (महाराष्ट्र) द्वारा वन मंडल छत्तरपुर के वन परिक्षेत्र वकरधाहा के वन कक्ष क्रमांक RF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & RF-302 के रकवा 382.131 है वनभृगि में वण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्मित से हीरा खनिज उत्खनन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि निम्नानुसार है :--

(i) वन भृमि :-

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	वन कक्ष क्र.	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
छतरपुर	वकस्वाहा	तिलई	RF-280, 281	40.947
		शहपुरा	RF-284	155.960
		सगोरिया	RF-285, 286	175.215
		दरदौनिया	RF- 302	5.238
		भड़ाटोर	RF-287	2.547
		ग्योलाई	RF-296	2.224
555		योग		382.131

(ii) वनभूमि के उपयोग का विवरण :-

क्रमांक	कार्य का विवरण	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1	माइनिंग लीज एरिया	364.00
2	एप्रोच रोड़	11,593
3	नाला डायवर्सन	6.537
	योग	382.131

- 3. प्रस्ताव वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/45288/2020 ऑनलाईन प्राप्त *हुआ है।
- 4. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना में वनमूमि से किसी व्यक्ति / परिवार को अन्यत्र विस्थापित नहीं किया जाना है।
- 5. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस पत्रक प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
- 6. आवेदक संस्था द्वारा बण्डर डायमण्ड परियोजना के माईनिंग प्लान की अनुमोदित प्रति प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत की गई है।
- 7. माईनिंग प्लान, भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यौरा, जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक MP/Chhatarpur/Diamond/MPLN/G-05/2020-21/951 दिनांक 04/09/2020 से अनुमोदित किया गया है । पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
- 8. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित रकबा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि का जियो रिफरेन्स मानचित्र जिसमें आवेदित स्थल के अक्षांश एवं देशांश की रीडिंग अंकित है, प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
- 9. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित रकवा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि को सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट स्केल 1:50,000 में दर्शाकर मानचित्र प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया है।
- 10 आवेदक संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3416 दिनांक 11/09/2020 से प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
- 11. प्रस्तावित रकबा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि इको क्लास—3 श्रेणी का वनक्षेत्र है जिसका घनत्व 0.6 है।
- 12 प्रस्तावित वन वनक्षेत्र में धवा, घोंट, मेनार, खैर, बहेडा, बेल, कांकर, केम, करोंदा, महुआ, सिरारू, पलास, रोनी, रेंझा, साज, सागौन, सेजा, दुधी, तेन्दू, अमलतास, आंवला, अचार, गुन्जा, गुरार, करधई, खटुआ, श्यामरा, सलैया, कल्ला, कैंथा, बरगद, पापड, धामन, हल्दू, विरौल, सुबबूल, व्याकुल, कारी, बीजा, कोसम, जामुन, अर्जुन, उमर, बैर, केवटी, पीपल, एवं खूजों कुल 2,15,875 वृक्ष विद्यमान है। वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट डालकर की गई है।
- 13 प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोरिपयर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर रिजर्व अन्तर्गत नहीं आता है।
- 14 प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य/बायोस्पियर रिजर्व/बाघ रिजर्व/ हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 01 कि.मी. की परिधि में नही आता है।
- 15 प्रस्तावित वनक्षेत्र, सरक्षित क्षेत्र पन्ना टाईगर रिर्जव (बफर) से 19.03 कि.मी. दूरी पर स्थित है तथा पन्ना वायरफोर रिजर्व 41 कि.मी. दूर है एवं कैन घडियाल अभ्यारण्य 90 कि.मी. दूर है। वन मंडल अधिकारी, छतरपुर द्वारा इसे 1:250,000 स्केल के मानचित्र में दर्शांकर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

- 16. प्रस्तावित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।
- 17. प्रस्तावित वन क्षेत्र के अंतर्गत कोई पारम्परिक स्थल/ऐतिहासिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
- 18. आवेदक द्वारा प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम की गई है।
- 19. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना प्रतिवेदित नहीं है।
- 20. न्यायालय कलेक्टर, जिला-धतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा आदेश क्रमांक 0002/ 31—59/व्यपवर्तन/2020—21 दिनांक 15/12/2020 से ग्राम कसेरा प.ह. बीरमपुरा तहसील बकरवाहा स्थित भूमि खसरा नं. 13/1 रकबा 382.131 हे. के स्थान पर खसरा नं. 13/1 में से 84.00 हे. खसरा नं. 26/1 में से 150.00 हे. खसरा नं. 364/1 में से 148.131 हे. कुल रकबा 382.131 हेक्टेयर गैरवनभूमि को मेसर्स एस्सैल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory afforesatation) हेतु आरक्षित की गई है।
- 21. आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैरवनभूमि का काफी भाग पूर्व से ही वृक्षों से आच्छादित है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दी गई गैरवनभूमि पर 1,00,000 पौधे रोपित किये जावेगें शेष 2,83,000 पौधे 283.00 हेक्टेयर विगडे वनों में रोपित किये जावेगे। वन मंडल अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना रकवा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory afforesatation) हेतु जिला छतरपुर के निम्न ग्रामों के कुल रकबा 383.00 हेक्टेयर की वनीकरण योजना राशि रूपये 158099574 / की संलग्न प्रस्तुत की गई है।

क्र0	जिला / वनमण्डल	ग्राम / परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक एवं कक्ष क्रमांक	रोपण हेतु प्रस्तावित रकवा	राशि रू०
1	छतरपुर	कसेरा :	13/1, 26/1, 364/1	100.00	58921531
2	छतरपुर	बकस्वाहा	पी198	60.00	20564220
3	छतरपुर	बकस्वाहा	पी198	60.00	20622844
4	छतरपुर	बक्सवाहा	पी.—267	34.00	12296159
5	छतरपुर	बक्सवाहा	पी198	60.00	23509597
6	छतरपुर	वक्सवाहा	पी.—251	69.00	22185223
	3			383.000	158099574

- 22 वन मंडल अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र का किये गये रथल निरीक्षण का 24 विन्दुओं पर आधारित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28/12/2020 प्रस्ताव में संलग्न है।
- 23. वन मंडल अधिकारी ,छतरपुर द्वारा अपनी अनुशंसा में वन / वन्यजीव प्रबंधन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव एवं वन्य प्राणियों के रहवासों के विखण्डन की संभावना एवं वन्यप्राणियों के आवागमन के संबंध समीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ के मतानुसार ही निर्णय लिया जा सकता का लेख करते हुये व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

- 24. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा प्रस्तावित वनक्षेत्र का दिनांक 02/01/2021 को किये गये स्थल निरीक्षण का 24 बिन्दुओं पर आधारित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 02/01/2021 प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
- 25. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा वन मंडल अधिकारी, छतरपुर द्वारा की गई अनुशंसा से सहमत होते हुये भाग-3 में प्रस्ताव में स्वीकृत देने की अनुशंसा की गई है।
- 26. नोडल अधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध द्वारा भाग-4 में प्रस्ताव में स्वीकृति देने की अनुशंसा की गई है।

राज्य शासन, वन विभाग द्वारा भाग-5 में प्रस्ताव में स्वीकृति देने की अनुशंसा की गई है। अतः प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबन्ध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक एफ-1/822/2021/10-11/ 578 प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक *05* /02 /2₂2₁

- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. –3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल
- 2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल छतरपुर, मध्यप्रदेश
- मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिडला ग्रुप, एस.के अहिर मार्ग, मुम्बई (महाराष्ट्र) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्नः—उपरोक्तानुसार। (अनु. क्र.–1 हेतु)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध) मध्यप्रदेश, भोपाल

Speed Post



भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in & ddgfirobhopal@gmail.com

F.No. 6-MPA008/2021-BHO/505

Date: 02.07.2021

To,

The DIGF (ROHQ)
Ministry of ENVIRONMENT, Forest &CC,
Indira Paryavaran Bhawan,
Aligan, Jorbagh Road,
New Delhi-110 003

Sub.: Diversion of 382.131 ha of land in Bauxwa range, Chhtrapur Forest Division, Sagar for Bunder diamond mining in favour of ESSEL Mining Company limited
Ref. No.: MoEF&CC, New Delhi letter No. FC-8-04/2021-FC dated 11th June-2021.

Sir,

Kind reference to above subject, I am directed to submit the site inspection report of IRO, Bhopal for further necessary action in the proposal please.

Encl.: Copy of SIR.

(Hare Ram Kumar)

Technical Officer (Forestry)

Site Inspection Report in respect of diversion of 382.131 ha of land in RF-280,281,284,285,287,296 and 302 in Bauxwa range, Chhtrapur Forest Division, Sagar for Bunder diamond mining in favour of ESSEL Mining Company limited.

The project was inspected by me on 30th April, 2021. During site inspection Shri Sunil Agrawal APPCF(LM) & Nodal Officer(MP), Shri Pritam lal Titare CCF Chhtrapur, Shri Anurag Kumar DFO Chhtrapur, Shri Rakesh Paliwal Project Head ESSEL and other officials of User Agency and Chhtrapur Forest Forest Division accompanied me.

1. Legal status of the forest land proposed for diversion:

Type of Land	Total ML/Project area (ha)
Reserve Forest	382.131
	382.131

Type of Land	Total Requirement (in ha)
Forest Land	382.131
Total	382.131

2. The land use shall be as follows

Work Name	Applied area (ha)
Mining area	364
Access road	11.59
Nallah	6.537
Total	382.131
	Mining area Access road Nallah

3. Details of component wise breakup

S	S.No. Component wise breakup		Area in ha
1	Mined out area		62.64
2	Side Burden & Waste Dump		138.31
3	Ore Stock Pi	le	3
4	Processing F	lant & Crushing Plant	10
5	Tailing Dum	p	66.34
6	Water Reser	voir & Dams	49.56
7	Infrastructur	e	10
8	7.5m wide safety zone along lease boundary		8.04
9	Mine Roads, Retention Walls and Drains		11.15
10	Magazine A	rea	1.54
11			0
12	Parking area	i	2.72
13	Intermediate	e Area	0.7
14			0
15	Nala diversion outside lease area		6.537
16	Mine Appro	oach Road	11.593
		Total	382.13

Total cost of the project at present rates:

The total cost of the project is Rs. 2500.00 Crores.

4. Wildlife:

Whether forest area proposed for diversion is important from wildlife point of view or not:

The applied area does not form part of any National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve.

The proposed forest land is at a distance of 19.03 Kms from the buffer zone of protected Panna Tiger Reserve and from the proposed eco-sensitive zone, 41 Kms from Panna Biosphere Reserve and 90 Kms from Ken Gariyal Sanctuary.



5. Vegetation:

The area comes under Deccan Peninsula Bio-geographic region of India. The type of Forest falls under Dry Tropical Forest with most of it being mixed deciduous forest. The area had large number of teak trees.

The said forest has been put under Eco-Value-Class-3 with density 0.6. The forest comprises of the following the species Baseline study of flora was carried out using quadrant method. A total 69 trees species have been noted in the area. The important species noted are Lannea Coromandelica (Gunja), followed by Tectona grandis (teak, Sagon), Madhuca indica (Mahua), Diospyros melanoxylon (Tendu), Anogeissues pendula (Dhaukra/Kardhai) Terminalia tomentosa (Saj/Saja), Lagerstroemia Parviflora (Seja/Lendia), Acacia Catechu (Khair). Terminalia tomentosa (Saja),

(a) Total number of trees to be felled. 215875

Effect of removal of trees on the general ecosystem in the area:

Felling of the trees from the forest area will induce soil erosion. Tree felling should be done in a phased manner.

(b) Important species:

The following species were found in this area

Anogeissus latifolia (Dhava), Randia dumetorum (Ghoat and Menar), Acacia catechu (Khear) Terminalia bellarica (Baheda), Aegle marmelos (Bel), Lannea coromandelica (Kanker), Mitragyna parvifolia (Kem), Madhuca indica (Mahua), Butea monosperma (Palas), Acacia leucophloea (Renjha), Lagerstroemia parviflora (Seja), Holarrhena antidysenterica (Dudhi), Diasporus melanoxylon (Tendu), Cassia fistula (Amltas), Embelica officinalis (Anvala), Buchanania lanzan (Achar), Garuga pinnata (Gunja), Bombax ceiba (Shyamra), Boswellia serrata (Saliya), Dillenia pentagyna (Kalla), Feronia limonia (Kentha), Ficus bengalensis (Bargad), Grewia tiliaefolia (Dhaman), Holoptelia integrifolia (Chiroal), Leucaena leucocephala (Subbool), Miliusa tomentosa (Kari), Pterocarpus marsupium (Beeja), Schleichera oleosa (Koram) Syzigium cumini (Jamun), Terminalia arjuna (Arjun), Stereospermum suaveolens (Pepal), Tectona grandis (saugon).

List of Fauna found in the proposed area Mammals of the core Zone :

S.No.	Common Name	Zoological Name	Schedule Wildflie (Protection) Act, 1972
1.	Axix asis	Cheetal	III
2.	Cervus unicolor	Sambar	III
3.	Sus scrofa	Wild pig	III
4.	Semnopithecus entellus	Common langur	II
5.	Macaca mulatta	Rhesus monkey	II
6.	Hystrix indica	Procupine	IV
7.	Lepus nigricollis	Indian hare	IV
8.	Herpestes edwarsii	Common mongoose	IV
9.	Canis aureus	Jakal	II

Number of trees of girth below 60 cm. 179838 Number of trees of girth above 60 cm. 36036

6. Background note on the proposal:

The particular block was explored and reconnaissance was accorded to Rio-Tinto company vide the following details.

Reconnaissance Permit

i) RP of Rio Tinto Mining/RP-2/2002 dated 19th June
 Area = 2450 sqkms Chhattarpur/Sagar/Damoh/Tikamgarh districts issued by GoMP.
 Prospecting Lease :

ii) Pl 1) of Rio tinto

Area = 25 sqkm.

PL of Rio tinto letter 4//12/2006/M-IV dated 27 June-2006. From Ministry of Mines, New Delhi.

PL 2) of Rio tinto

Prospecting Lease: Area 45 sqkms.

4/11/2006/M-IV dated 24th April 2007 from Ministry of Mines, New Delhi

iii) ML of Rio Tinto (Letter no 4/107/2009/M.IV dated 17/11/2011 Ministry of New Delhi.)

Area = 954 ha (9.54 sqkms).

Mining Lease.

iv) ML grant In Auction to EMII

Area = 364 ha (3.64 sqkm)

LoI dated 19/12/2019 mineral resource department Govt of MP.

The original lessee Rio Tinto conducted initial survey and prospecting in this area. MoEF vide ref no 8-49/2006FC permitted prospecting over 2329.75ha of land. After conducting prospecting, Rio Tinto handed over all possessions including extracted diamond, processing plant, residential colony(raised over 10.0ha) of non forest land to state government and left. The extracted diamonds were sold in auction by diamond officer Panna and revenue remitted to GoMP account.

The present lessee has taken part in auction conducted by GoMP and bid the highest amount and entered into LoI with the MP. Bunder Diamond Block encompasses 5.70 Mt of Kimberlite/Lamproite reserves containing ~ 34 Million Carats of rough Diamonds.

Bunder Diamond Project is conceptualized adopting mechanized opencast mining to excavate and process 5.0 Mtpa of Kimberlite and produce ~ 3.2 Million Carat of Diamonds per annum. The project shall encompass mining, processing, & associated infrastructure. Bunder Diamond is one of the most important and significant discoveries in last 25 years across globe, and the first diamond discovery in India for over 40 years. It is one of the few advanced stage projects in last 15 years likely to become functional globally in immediate future. Finding economic diamond deposits is difficult, over the last 140 years, almost 7,000 kimberlite pipes have been sampled by geologists, about 1,000 of which have been diamondiferous. However, only about 60 were sufficiently rich in diamond to be economically viable (0.86% only), & just 7 could be referred as "Tier 1" deposits with more than US\$20 Billion worth of reserves (0.01%).

7. Compensatory afforestation:

CA land has been identified in 3 patches. Out of total 382.131 ha land, 84.00 ha land lies in Khasara No. 13/1, 150.00 ha in Khasara No. 26/1, 148.131 ha in Khasara No. 364/1 of village Kasera, Buxwaha Tehsil, in Chhattarpur District.

Village	Khasara No.	Area (ha.)	
Kasera	364/1	148.131	
Kasera	26/1	150.00	
Casera 13/1		84.00	
lej	Total	382.131	

(a) Whether land for compensatory afforestation is suitable from plantation and management point of view or not: The approved compensatory scheme suggest plantation of 383000 Trees i.e. -1.8x Times the trees enumerated in the proposed area for diversion.

The land made available for compensatory afforestation is covered partly with vegetation. Thus about 100,000 trees will be planted in area reserved for compensatory afforestation and remaining 283,000 trees will be planted degraded forest of 283 ha. The DFO has submitted compensatory afforestation scheme over an area of 383 ha for an amount of RS. 15.8099 Crores.

- (b) Whether land for compensatory afforestation is free from encroachment/other encumbrances: Yes.
- (c) Whether land for compensatory afforestation is important from Religious/Archaeological point of view:

 No.
- (d) Land identified for raising compensatory afforestation is in how many patches, whether patches are compact or not: The CA area is in 03 patches in Chhattarpur Forest division.
- (e) Map with details: Enclosed in the proposal.
- (f) Total financial outlay: Cost of Compensatory afforestation over 383.00 ha Non-Forest land /Plantable Degraded Forest Land under of Chhattarpur Forest Division is Rs. 15.8099 Crores.
- 8. Whether proposal involves violation of Forest (Conservation) Act, 1980 or not. If yes, a detailed report on violation including action taken against the concerned officials:

No.

9. Whether proposal involves rehabilitation of displaced persons. If yes, whether rehabilitation plan has been prepared by the State Government or not:

No. The project does not involve displacement of any human habitation.

10. Reclamation plan:

Post closure of the mining operations, the area will be reclaimed. Mine Reclamation plan has been approved by the Indian Bureau of Mines (BM).

Void left after closure of the mine and water reservoir created will act as water body covering area around 112 ha.

EMIL in addition to this may volunteer additional plantation.

Year	Dun	nps	Worke Benc	S-man-	Green	Belt*	To	tal
	Area Ha.	Trees	Area Ha.	Trees	Area Ha.	Trees	Area Ha.	Trees
1	0	0	0	0	2.88	5,760	2.88	5,760
2	0.27	540	0	0	2.80	5,600	3.07	6,140
3	0.23	460	0	0	2.40	4,800	2.63	5,260
4	0.95	1,900	0	0	0	0	0.95	1,900
5	3.20	6400	0	0	0	0	3.20	6,400
Sub total	4.65	9.300	0	0	8.08	16,160	12.73	25,460
6 to LOM	200.0	4,00,000	24.5#		0	0	224.5	4,00,000
Total	204.65	4,09,300	24.5		8.08	16,160	237.23	4,25,460

After closure of the operations more than 60% of the area (220 ha) diverted for the project will be transformed into forest with suitable plantations.

Post closure and successful reclamation of mine entire lease area will be handed over back to the forest department. Details of progressive reclamation plan are available in mining plan chapter 8.3 page no. 161 to 170.

(20)

Details and financial allocation:

As per mine closure plan, in page no. 170 the details are available in page no. 173 table no. 1.11 the details of financial allotment for reclamation as well as other area given financial assurance @3 lakhs per ha.

Details on catchment and command area under the project:

NA

Catchment area treatment plan to prevent siltation of reservoir:

NA

12. Cost benefit ratio:

The cost benefit ratio comes to 1:526.

13. Recommendations of the Principal Chief Conservator of Forests/State Government:

Recommended.

14. Recommendations of Dy. Director General of Forest (Central) along with detailed reasons:

This is a site specific project and the deposit has been thoroughly investigated. The case is recommended for diversion.

- 15. Dy. Inspector General of Forests shall give detailed comments on whether there are any alternative routes/alignment for locating the project on the non-forest land: NA
- 16. Utility of the project:

Numbers of Scheduled Caste/Scheduled Tribes to be benefited by the project:

As reported the project is likely to generate direct employment of about 400 persons in addition to indirect employment during the mining operations.

- 17. Whether land being diverted has any socio-cultural/ religious value:
- (a) No, the land being diverted has no socio-cultural/ religious value.
- (b) Whether any sacred grove or very old growth trees/forests exist in the areas proposed for diversion:

No, there is absence of any sacred grove or very old growth trees/forests in the areas proposed for diversion.

(c) Whether the land under diversion forms part of any unique ecosystem:

No, the land under diversion does not form part of any unique ecosystem.

18. Situation with respect to any Protected Area:

The area is not part of any Biosphere Reserve, National Park, Sanctuary. It is not in ESZ of any sanctuary or national park. The proposed forest land is at a distance of 19.03 kms from the buffer zone of protected Panna Tiger Reserve and from the proposed ecosensitive zone, 41 kms from Panna Biosphere Reserve and 90 kms from Ken Gariyal Sanctuary.

19. Any other information relating to the project:

This project will be helpful to the local population in terms of employment and reduce the dependence of our country on imports and save huge foreign exchange. The project will generate huge revenue for the country. The mining plan and certificate of FRA as well as No objection from Gram Sabha has been received by the UA.

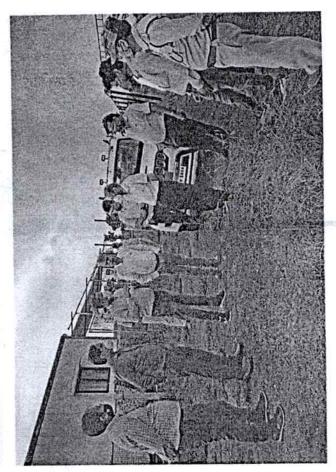
STATESTA (Subrat Mohapatra, IFS)

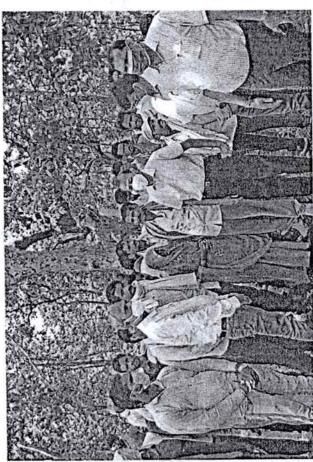
Dy. Director General of Forest (Central)

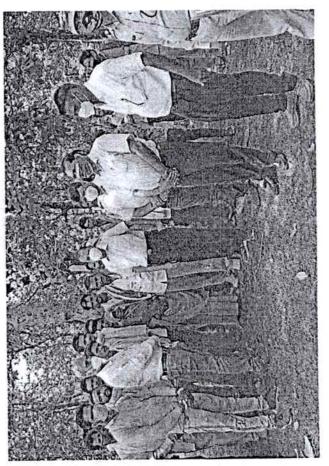
LIST OF ANNEXURE

S.No.	Particulars
1.	Photographs of Field Visit
2.	A copy of Ministry's reference no. 8-49/2006-FC dated 05/07/2006
3.	Query raised by Ministry's and reply furnished by Nodal Officer, Madhya Pradesh
4.	Reclamation plan (2 plates)















F.No. 8-49/2006-FC Government of India Ministry of Environment and Forests

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003 Date: 05.07.2006

To

The Principal Secretary (Forests) Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.

Sub: Prospecting of Diamonds over 2,329.75 ha of forest land in Chattarpur Forest Division in favour of M/S ACC Rio Tinto Exploration Ltd. in district Chattarpur, Madhya Pradesh.

Sir

I am directed to refer to letter no. F-1/402/06/10-11/910 dated 06.05.2006 of Nodal Officer, Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted under Section-3 of the aforesaid Act.

- After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendation of the above mentioned Advisory Committee, the Central Government hereby conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for prospecting or diamonds over 2,329.75 ha or forest land in Chattarpur Forest Division in favour of M/S ACC Rio Tinto Exploration Ltd. in district Chattarpur, Madhya Pradesh subject to fulfilment of following conditions:-
 - This permission shall not be construed as any commitment on part of Central Government for diversion of forest land for mining lease.

No trees will be felled.

(iii) After completion of prospecting, all bore holes will be filled up.

State Government will institute a monitoring mechanism to regularly review progress of prospecting.

Prospecting shall be completed in 2 years.

Yours faithfully,

सस्य-प्रतिलिपि

लेखाधिकारी प्रधान पुरान यम स Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

- The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh,
- Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
- The CCF (Central), Regional Office, Bhopal
- User Agency RO (HQ)/Monitoring Cell, MoEF, New Delhi
- Guard File

Assistant Inspector General of Forests

(27)

F. No. 8-49/2006-FC Government of India Ministry of Environment and Forests (F.C. Division)

> Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New DeIhi -- 110 003. Dated: 05th June, 2009.

To

The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Sub: Prospecting of Diamonds over 2329.75 ha of forest land in Chhatarpur Forest Division in favour of M/s ACC Rio Tinto Exploration Limited in Chhatarpur district of Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to Government of Madhya Pradesh's letter No. F-1/402/06/10-11/910 dated 06.05.2006 on the above mentioned subject, wherein prior approval of the Central Government for prospecting of Diamonds over 2329.75 ha of forest land in Chhatarpur Forest Division in favour of M/s ACC Rio Tinto Exploration Limited in Chhatarpur district of Madhya Pradesh, was sought, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The said proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

- 2. After careful consideration of the proposal of the State Government of Madhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government hereby grants approval for prospecting of Diamonds over 2329.75 ha of forest land in Chhatarpur Forest Division in favour of M/s ACC Rio Tinto Exploration Limited in Chhatarpur district of Madhya Pradesh, subject to the fulfilment of the following conditions:
 - All the conditions prescribed in earlier letter dated 05.07.2006 allowing prospecting of Diamonds over 2329.75 ha of forest land in Chhatarpur Forest Division in favour of M/s ACC Rio Tinto Exploration Limited in Chhatarpur district of Madhya Pradesh.
 - The permission shall be valid for the period of Prospecting Licence given under MMRD Act, 1956.
 - Pit No. 11 will be enlarged from 40 sq. m. to 500 sq. m. with the depth of 5 metre.
 - Eight large diameter core holes of diameter 8" and 250 m. depth with a drilling site of 30 m x 30 m shall be allowed.

्रान्त्र्य पूर्वे (ग्रान्त्र्या धूर्वे) लेखाधिकारी क्षाणीकार पुट्ट का ता (का-मू-मन्द्रा)

- Five slim core holes of 79/96 /192 mm dia having depth 350 m. and drilling site of 10 m x 10 m shall be allowed
- The felling of required 48 trees will be done only if it is required and 6. under supervision of State Forest Department.
- Adequate protection measures will be taken to mitigate the impact of drilling on surrounding forest and wildlife areas. It will be done in 7. consultation with the State Forest Department and its wildlife wing.
- A study may be conducted for adverse impact of diamond mining on 8. surrounding flore and fauna.

Yours faithfully,

(B.K. Singh) Sr. Assistant Inspector General of Forests

- The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Copy. to:-
- The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh,
- The CCF(Central), Regional Office, Bhopal. 3.
- 4.
- User Agency. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi. 5.
- Guard File. . 6.

(B.K. Singh)

Sr. Assistant Inspector General of Porests

F. No. 8-49/2006-FC (vol.) Government of India Ministry of Environment and Forests

(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. Dated: 10th June, 2011

To,

The Principal Secretary (Forests), Government of Madhya Pradesh,

Proposal to obtain prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980, for drilling of additional 143 bore holes at identified locations in 2329.75 ha. forest land located in 18 compartments in Buxwaha Range in Chhatarpur district of Madhya Pradesh by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited for prospecting of diamond ore.

I am directed to refer to Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Land Management) and Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh's letter No. F-1/402/ 2006/ 10-11/444 dated 08.02.2011, on the above mentioned subject, and to say that the said proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

After careful consideration of the proposal of the State Government of Madhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government hereby accords approval for drilling of additional 143 bore holes as per the size and location indicated in the proposal submitted by the State Government of Madhya Chhatarpur district of Madhya Bradach by M. Die Tiete B. Buxwaha Range in for prospecting of diamond ore, subject to fulfilment of the following conditions:-

The drilling of the additional 143 bore holes shall not result in felling of any tree; (i)

The samples collected during the prospecting shall be used purely for investigation purposes and shall in no case be used for trade or commerce purpose; (ii)

To minimize disturbance to the wildlife, user agency shall take all possible measures to minimize noise during drilling operations and halt the drilling activities during night and during such periods in the day as may be advised by the Chief Wildlife (iii) Warden, Government of Madhya Pradesh;

The State Forest Department shall deploy adequate staff to supervise the activities to be undertaken by the user agency to prevent any damage to the flora (especially the fresh regeneration), fauna and also to prevent felling of trees during drilling of holes and movement of equipment;

खार्स. प्रधान ^व

- After completion of the prospecting all bore holes shall be completely filled up; and (v)
- The work for prospecting including filling up of the bore holes shall be completed on (vi) (vii) or before 05.09.2011.

SAL

2

(H.C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

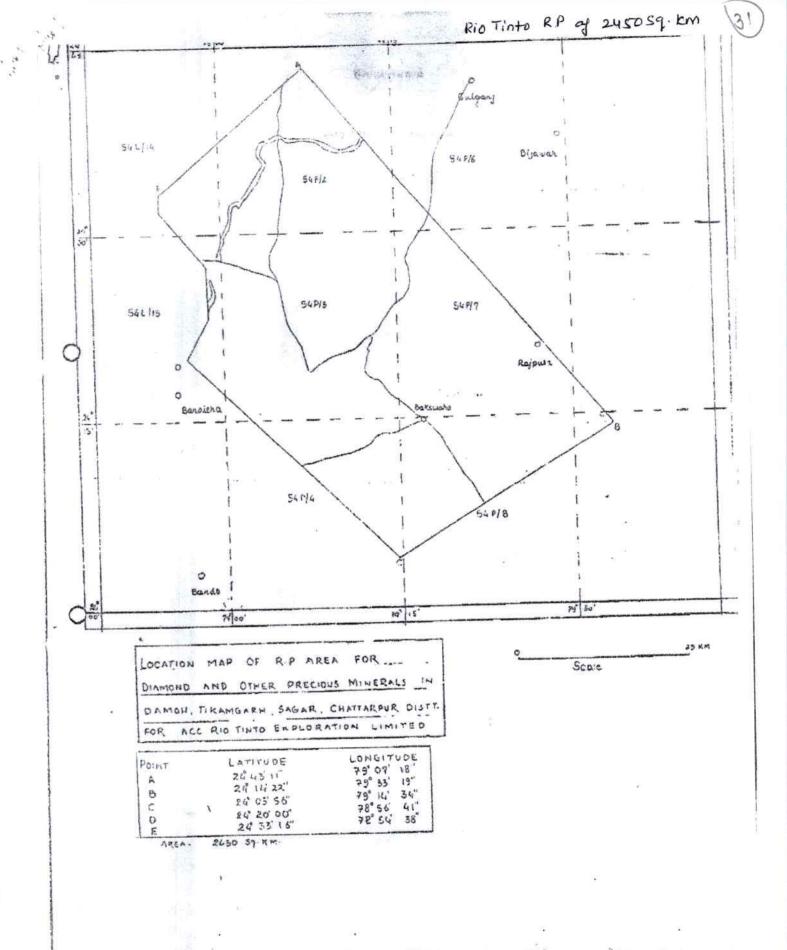
- The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
- The CCF (Central), Regional Office, Bhopal.
- Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
- Guard File.

10/06/~17 (H.C. Chaudhary)

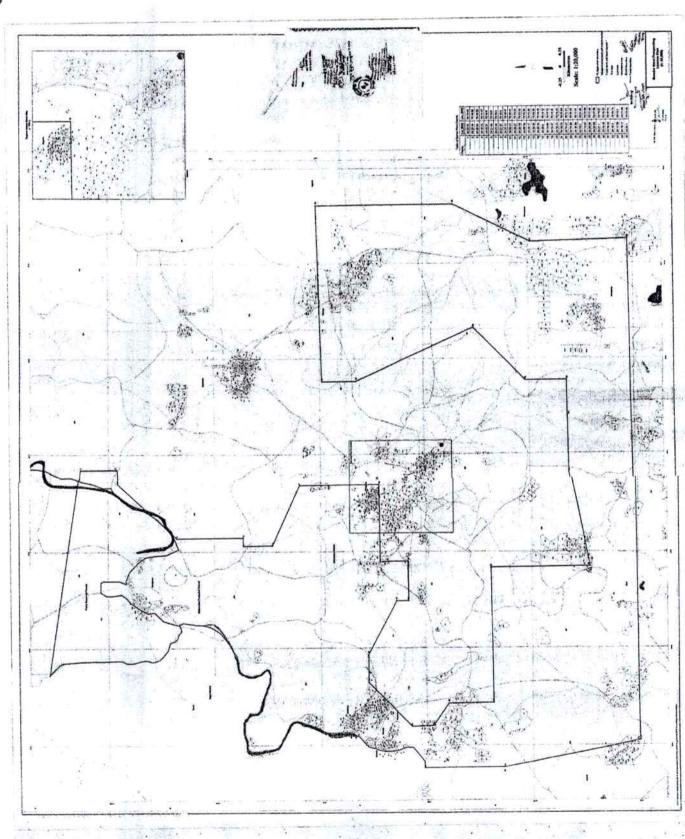
Assistant Inspector General of Forests

म.प्र., भोपाल

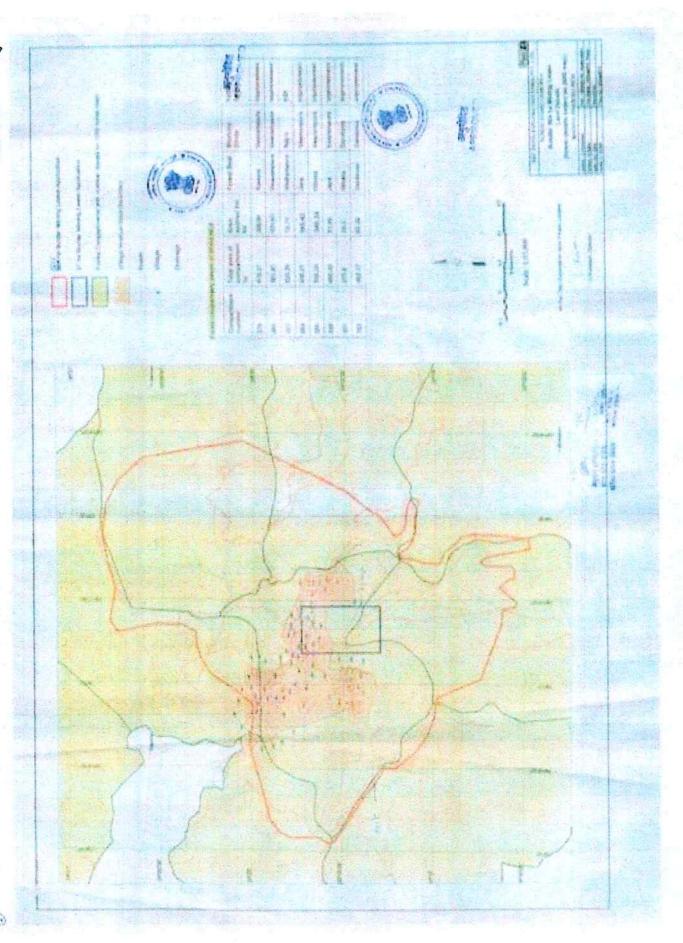
छार्या. प्रशत र



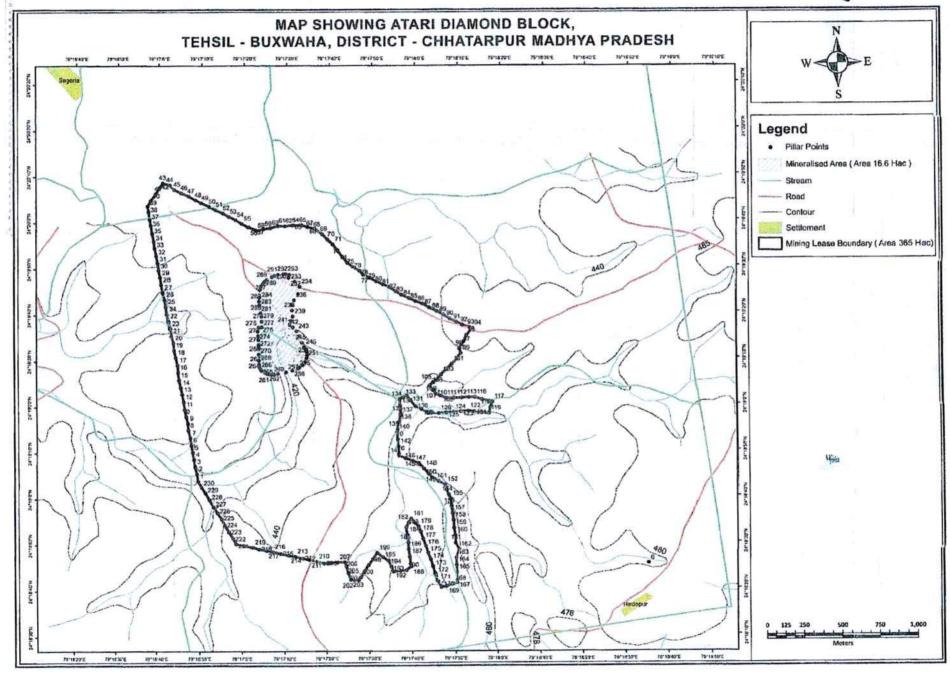
į



Rio Tinto Ped 4059 am









कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्ष्मांक/एफ-1/822/2021/10-11/2034 भोपाल, दिनांक 28-06-2021

प्रति.

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नारत सरकार, प्यावरण वन एवं ज इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषय:—वन मंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा के RF-280, 281, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धति से हीरा उत्खनन हेतु – मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 8-04/2021-FC दिनांक 12/04/2021

--0--

कृपया प्रकरण में आपने संदर्भित पत्र से निम्न पांच बिन्दुओं पर जानकारी चाही है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी का विवरण
1	The component wise breakup of the proposal shows that the 24.96 ha forest has been proposed for crushing and processing plant, infrastructure, magazine area, parking area. intermediate area ect. which are non-site specific activities. Justification for not carrying out these activities on non-forest shall be submitted.	इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2021 से स्थिति स्पष्ट की है। आवेदक संस्था का पत्र संलग्न है।
2	The KML file of the degraded forest land identified for completing the target of Compensatory Afforestation shall be submitted.	गैरवनभूमि का काफी भाग पूर्व से ही वृक्षों से आच्छादित है। अतः गैरवनभूमि पर 1,00,000 पौधे रोपित किये जावेगें एवं शेष 2,83,000 पौधे 283.00 हेक्टेयर बिगड़े वनों में रोपित किये जावेगें। बिगड़े वनों में पौधे 05 स्थलों पर रोपित किये जायेंगे, जिनकी KML file संलग्न है।
3	The component wise breakup of proposal shows that 62.64 ha of area for Mined out area. The clarification shall be submitted that whether it is a previously mined out area or else a fresh area.	17.04.2021 से स्थिति स्पष्ट की है। आवदक संस्था का पत्र संलग्न है।

The Survey of India toposheet map of proposed CA clearly shows an overlap with protected forest. Therefore, the concerned CF/CCF shall submit a report in this regard by inspecting the site proposed as CA.

वन मंडल अधिकारी, छतरपुर द्वारा पत्र दिनांक 10/6/2021 से अवगत कराया है कि आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) के मौके पर निरीक्षण से स्पष्ट रूप से वन सीमा से लगी हुई उपलब्ध है।

इस संबंध में अनुरोध है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जब भी इस प्रस्ताव में स्थल का निरीक्षण किया जायेगा तब उन्हें क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि का स्थल निरीक्षण भी करवा दिया जायेगा।

The State Government vide letter
No. F-1/822/2021/10-11/630 dated
10.02.2021 informed that the State
Government has not recommended
the instant proposal. In view of this,
the updated Part-V with clear view
of State Government shall be
uploaded on e-portal.

इस संबंध में लेख है कि प्रस्ताव में राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र—5 में प्राप्त हो गई थी। तदानुसार इस अनुशंसा को प्रस्ताव के भाग—2 में अपलोड कर प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 05.02.2021 को अग्रेषित किया गया है।

तत्पश्चात राज्य शासन के अधिकारियों से चर्चा में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में अभी राज्य शासन का प्रशासकीय अनुमोदन नहीं हुआ है। तदानुसार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.02.2021 से इस संबंध में भारत सरकार को अवगत कराया गया था।

प्रस्ताव में राज्य शासन का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 08.03.2021 से भारत सरकार को प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था तथा राज्य शासन की

अनुशंसा प्रपत्र-5 में उपलब्ध कराई थी।
परिवेश पोर्टल पर राज्य शासन की अनुशंसा
अपलोड होने पर उसमें परिवर्तन करना संभव
नहीं होता है। अतः अनुरोध है कि NIC के माध्यम
से इसे पोर्टल पर अपलोड करवाने का कष्ट
करें। राज्य शासन की अनुशंसा की प्रति पुनः
संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक / एफ-1 / 822 / 2021 / 10-11 / 2035

भोपाल, दिनांक 28-06-2021

- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं.-3, ई-5 रविशंकर नगर, भोपाल
- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश 2. %
- वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, छतरपुर, मध्यप्रदेश
- मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला ग्रुप एस.के. अहीर मार्ग, 3. मुम्बई (महाराष्ट्र) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन स्रिक्षक (भू-प्रबन्ध) मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय सामान्य, वन मंडल छत्तरपुर (म. प्र.)

जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 © 07682-245316 (O.), 245316 (Fax) E-mail: <u>dfotchtpur@mp.qov.in</u>

क्रमांक / मा.चि. / 2021 /868 रूप्रति, छतरपुर, दिनांक 1º/6/2)....

अर्पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल (म0 प्र0)

विषय:— वनमंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा के वन कक्षक्रमांक RF- 280, 284, 286, 287, 296, 302 के कुल रकवा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि में बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धित से हीरा उत्खनन का मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/45288/2020

सन्दर्भ :- आपका पत्रक्रमांक / एफ-1 / 622 / 2021 / 10-11 / 1610 भोपाल दिनांक 25.05.2021

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रक्रमांक/एफसी-1-04/2021-एफसी दिनांक 12.04.2021 से 04 बिन्दुओं में से बिन्दुक्रमांक 02 एवं 04 की जानकारी चाही गई थी, जो निम्नानुसार है :-

बिन्दुक्रमांक 02 :- क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनक्षेत्र की के.एम.एल. फाइल 02 प्रतियों में तैयार कर संलग्न है।

बिन्दुक्रमांक 04:— क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) के मौके पर निरीक्षण से स्पष्ट रूप से वन सीमा से लगी हुई उपलब्ध है।

उपरोकतानुसार जानकारी आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अनुराग कुमार) वन गण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल छतरपुर

पृष्ठां. क्रमांक / मा.चि. / 2021 / छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

वन मण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल छतरपुर

EUIT A

अण्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोगाल २ १-6-२)

46 Ayaz Khan DM File 2021/Latter 2021

-	190	N	iwar 198	A	1	A CONTRACTOR
稳	N24	15	31.65	E79	04	58.72
2	N24	15	16.32	£79	04	46.23
3	N24	15	24.56	E79	04	26:34
4	- N24	15.	30.95	E79	04	29.85
5	N24	415	31.81	E79	04	27.73
6	N24	15	35.42	E79	04	27.48
7	N24	15	37.71	E79	04	19.68
8	N24	15	40.54	E79	04	19.34
. 9	N24	15	43.63	E79	04	13.08,
10	.N24	15	50.93	E79	04	30.37
. 11	N24	15	48.6	E79	, 04	40.85
12	N24	15	48.09	E79	04.	46.19
13	N24	15	44.18	E79	04	41.2
Children.	THE PERSON NAMED IN	THE PERSON NAMED IN				A Land Company

4	100	N	iwar 198	3 B		A	7
1	N24	15	16.08	E79	04	45.62	7.77
2	N24	15	12.83	E79	04	40.42	1000
3	N24	15	9.69	E79	04	39.41	To the
4	N24	15	7.85	E79	04	36.59	
5	N24	15	5.61	E79	04	39.67	1
6	N24	15	3.63	E79	.04	38.94	1
- 7	N24	15	1.76	E79	04	41.5	1
8	N24	15	1.49	E79	04	46.31	١
9	N24	14	56.41	E79	.04	49.07	١
10	N24	14	49.91	E79	04	49.02	I
11	N24	14	47.3	E79	04	50.93	I
12	N24	14	47.18	E79	,04	17.62	l
13	N24	14	50.27	E79	04	15.8	١
14	N24	15	0.53	E79	04	29.67	l
15	N24	15	3,86	E79	04	28.41	100000
16	N24	15	6.39	E79	04.	21.75	
17	N24	15	6.58	E79	04	18.21	
18	N24	15	19.68	E79	04	16.84	
19	N24	15	21.72	E79	04	18.07	1
20	N24	15	22.9	E79	04	21.05	
21	N24	15	25.95	E79	04	20.82	
		THE RESERVE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		_		

	770	N	iwar 198	C		
1	N24	14	13.65	E79	04	24.42
2	N24	14	20.4	E79	04	11.29
3	N24	14	46.58	E79	04	21.8
4	N24	14	46.29	E79	04	50,58
5	N24	14	35.06	E79	04	49.28
6	N24	14	31.08	E79	04	43.28
7	N24	-14	27.02	E79	04	41.84

- 神秘を立てた

		3.8	Kasera	267	web with	Service Services
1	N24	19	3.12	E79	22	45.28
2.	N24	19	29.07	E79	22	54.99
3	N24	19	14.03	E79	23	14.07
4	N24	19	2.34	E79	23	7.5
36			Khejra	251		
1	N24	12	16.39	E79	22	40.73
?	N24	11	42.02	E79	22	55.68
3	N24	11	43.31	E79	22	44.77
12	N24	11	44.42	E79	22	44.1
1	N24	11	46.37	E79	22	37.55
3	N24	11	46.72	E79	22	31.74
30	N24	11	44.84	E79	22	29.09
i i	N24	11	48.32	E79	22	23.54
7	N24	11	47.65	E79	22	20.21
)	N24	11	52.49	E79	22	15.64
7	N24	11	57.32	E79	22	15.78
100	N24	11	58.13	E79	22	20.01-
	N24	,12	6.05	E79	22	20.52
100	N24	12	5.91	E79	22	18.24
整	N24	12	10.86	E79	22	13.42
;	N24	12	11,94	E79	22	14,11







#:MIL/Bunder/HO/2021/04

17 April 2021

The APCCF (Land Management) & Nodal Officer Forest Department, Government of Madhya Pradesh Satpuda Bhawan Bhopal, Madhya Pradesh

Subject: Proposal of Forest diversion bearing number FP/MP/M1N/45299/2020 with respect to Bunder Diamond Block for opencast mining of Diamonds in 382.131 Ha at forest compartment numbers 280, 284, 285, 286, 287, 296 & 302 in Buswaha Range of Chhatarpur Forest Division.

Reference: Letter from your office bearing number F-1/622/2021/10-11/1371 dated15-April-2021 with respect to the subject matter.

Dear Sir,

With reference to your letter number F-1/622/2021/10-11/1371 dated 15 April 2021, seeking response to point 1 & point 3 on the EDS queries sought by MoEF&CC. New Delhi vide its letter number FC-8-04/2021 dated 12 April 2021, our response to these points is under: -

Point 1: Component wise breakup of the proposal shows that the 24.96 Ha of Forest land has been proposed for crushing & processing plant, infrastructure area, magazine area, parking area, intermediate area etc. which are non-site specific activities. Justification for not carrying out these activities on non-forest area shall be submitted.

Response:

- The Bunder Diamond Block is an integrated mining project and involves mining, crushing, processing. Diamond recovery, sorting, these activities along with ancillary infrastructure are site specific & integral part of mining operations & mineral recovery process. Kimberlite being the Diamond bearing rock will be mined & processed for recovery of Diamonds within the crushing and processing facilities located within mining lease area. The ancillary infrastructure is site specific and proposed over an area of 24.96 Ha within Mining Lease being an integral part of mining operations.
- Mining plan is prepared under the provisions of MMDR Amendment Act 2015, MCR 2016, MCDR 2017 & subsequent guidelines pursuant to these Act and Regulations. IBM Manual on Appraisal of Mining Plan 2014 provides the guidelines for preparation and approval of Mining Plan. Point no 14 in page 17 of the appraisal document states that "In view of the Hon'ble Supreme Court Judgment dated 21.04.2014 in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012 filed by Goa Foundation vrs Union of India and Others all activities like waste dumping, stacking ore, subgrade, mineral rejects, beneficiation, depositing tailings are to be within the lease area".
- Clause 9.1 of Standard Mine Development Agreement of Tender document of Bunder Project mandates "Limited Mining Rights: Pursuant to this agreement the Successful Bidder shall be entitled to conduct mining operations only in the Lease Area and shall not be entitled

Essel Mining & Industries Ltd.

Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.

T: +9122 6652 5000/2499 5000 F:+9122 5562 5831/2499 5831 E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.

Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728



- to conduct the mining operations in any other area outside the Lease Area. The rights granted to the Successful Bidder herein to conduct mining operations are exclusive within the Lease Area.
 - The mining plan for the project is approved by Regional Controller, Indian Bureau of Mines,
 Jabalpur in exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub section (2) of Section 5
 of the MMDR Amendment Act 2015. The Regional Controller have approved the Mining
 Plan including Progressive Mine Closure Plan submitted under Rule 16 of Mineral Concession
 Rules 2016.
 - Taking cognizance of the IBM guidelines, above judgment and MDPA conditions the mining plan is conceptualized by setting up of all mining activities and associated infrastructure being site specific within the Mining Lease area.
 - To further add the infrastructure area of 24.96 Ha (crushing & processing plant, infrastructure area, magazine area, parking area, intermediate area etc.) will be fully reclaimed and rehabilitated/afforestation by multi layered species and handed over to the forest department.

Point 3: The component wise breakup of the proposal shows 62.64 Ha of area for Mined Out area. The clarification shall be submitted whether it is previously mined our area or fresh area.

Response:

• Bunder Diamond Block is a fresh grant and a Greenfield mining project auctioned by GoMP and as such there is no mined out area as of now. The component wise breakup stated in Form A (Part I) relates to the conceptual land use/End of Mine land use as per Approved IBM Mining Plan and do not refer to any previously mined our area. At the end of mine lease period an area of 62.64 ha will be excavated for the purpose of Mining. The area will be rehabilitated as per Approved Mine Plan and handed over to forest department after completion of mining lease period.

Our responses may be suitably incorporated in your consolidated response to the MoEF&CC on the matter. We look forward for your earliest action in this regard for propelling the proposal forward.

Thanking you

For Essel Mining & Industries Limited

d Findus

Krishan Kant Sinha General Manager

Essel Mining & Industries Ltd.
Adityu Birla Center, 'A' Wing, 1" Floor, S.K. Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030. India.
T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com/www.esselmining.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.

Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ-1 / 622 / 2021 / 10-11 /874 भोपाल, दिनांक % - 3-2-1

प्रति.

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप, वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003

विषय:— वन मंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा के वन कक्ष RF- 280, 284, 285, 286, 287, 296, 302 के रकबा 382.131 हे. वनभूमि में बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धित से हीरा उत्खनन का मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का प्रस्ताव—FP/MP/MIN/45288/2020.

संदर्भ:--1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ--1/622/2021/10--11/630 दिनांक 10/02/2021

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र.
 04/2021-FC दिनांक 02/03/2021

उपरोक्त संदर्भ पत्र क्रमांक –1 से आपको मेसर्स एैस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई का छतरपुर जिले में बण्डर डायमण्ड हीरा उत्खनन रकबा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव राज्य शासन की अनुशंसा त्रृटिवश अपलोड हो जाने के कारण इस प्रस्ताव को वापस करने या राज्य शासन के निर्देश प्राप्त होने तक इसे Hold पर रखने का अनुरोध किया गया था।

आपके संदर्भ पत्र क्रमांक—2 द्वारा इस प्रस्ताव को राज्य शासन स्तर पर वापस किया गया है। आपके द्वारा यह भी जानकारी चाही गई है कि जब प्रस्ताव में राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित थी तो प्रस्ताव भारत सरकार को क्यों प्रेषित किया गया।

इस संबंध में अनुरोध है कि इस प्रस्ताव में राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र— V में तत्कालीन सचिव, वन श्री एच.एस. मोहन्ता द्वारा दिनांक 04/02/2021 को की जाकर इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया था। राज्य शासन का प्रपत्र—V में अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में पदेन सचिव, वन से दूरभाष पर हुई चर्चा में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव पर माननीय वनमंत्रीजी द्वारा आवेदित वनक्षेत्र की पन्ना टाइगर रिजर्व से दूरी बाबत् एक जानकारी चाही गई है तथा सम्बन्धित लिपिक द्वारा त्रुटिवश प्रपत्र—V में सचिव, वन की अनुशंसा हस्ताक्षरित कराकर इसे हमारे कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया है। तदानुसार इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.02.2021 से इस प्रस्ताव को Hold पर रखने या वापस करने का अनुरोध किया गया था। इस त्रुटि के लिये यह कार्यालय क्षमा प्रार्थी है।

44

इस प्रस्ताव पर राज्य शासन, वन विभाग की अनुशंसा दिनांक 03/03/2021 से प्राप्त हो गई है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है। पूर्व में दिनांक 04.02.2021 को भाग—v में अपलोड की गई राज्य शासन की अनुशंसा तकनीकी कारणों से विलोपित नहीं हो पा रही है। अतः राज्य शासन द्वारा दिनांक 03/03/2021 से प्राप्त अनुशंसा इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

ردر (सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ−1 / 622 / 2021 / 10−11 /875 प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 8-03-21

- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं.–3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल।
- 2. मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला ग्रुप, एस.के. अहीर मार्ग, मुम्बई।

की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संलग्नः—उपरोक्तानुसार (अनु. क्र.–1 हेतु)

> अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

TH

V-KPR

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

"	-	1.5	175	
18				
सिफारिश	भाग "ग"	402	टिष्पणी की	
क	"ख्" या भे किसी	कीम	शिष्ट ि	
सरकार	मान "च्"	न् न	टिप्पणियों पर विशिष्ट ि	
साज्य	(उपयुक्त	可是可可	टिप्पणिय	जार)
18				

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल छतरपुर के परिक्षेत्र बकरवाहा के रकबा 382.131 हेक्टेयर वनभूमि में बण्डर डायमण्ड ओपन कास्ट पद्धति से हीरा उत्खनन कार्य करने का मेसर्स ऐस्सेल माईनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

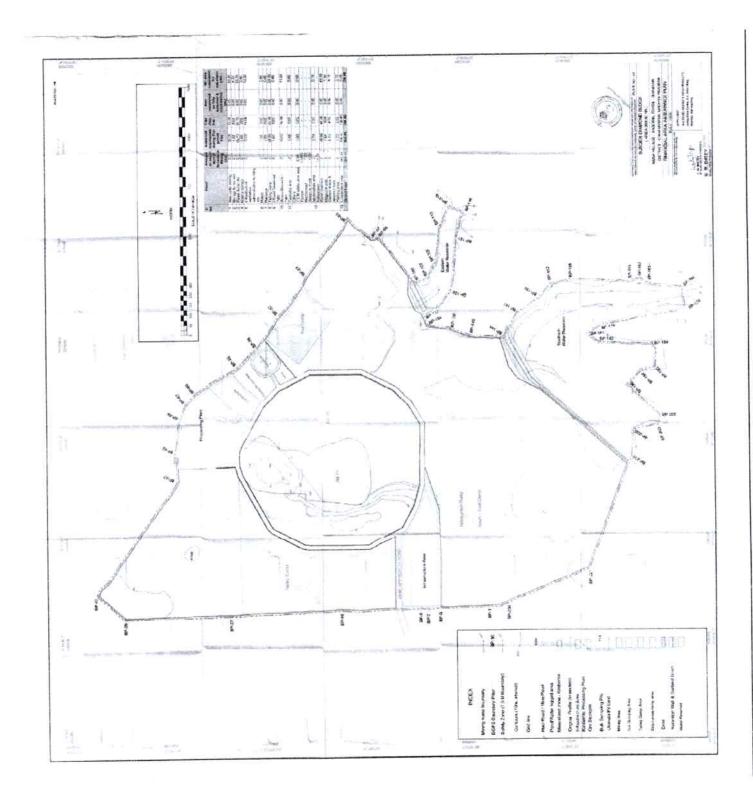
दिनांक: .03.2020

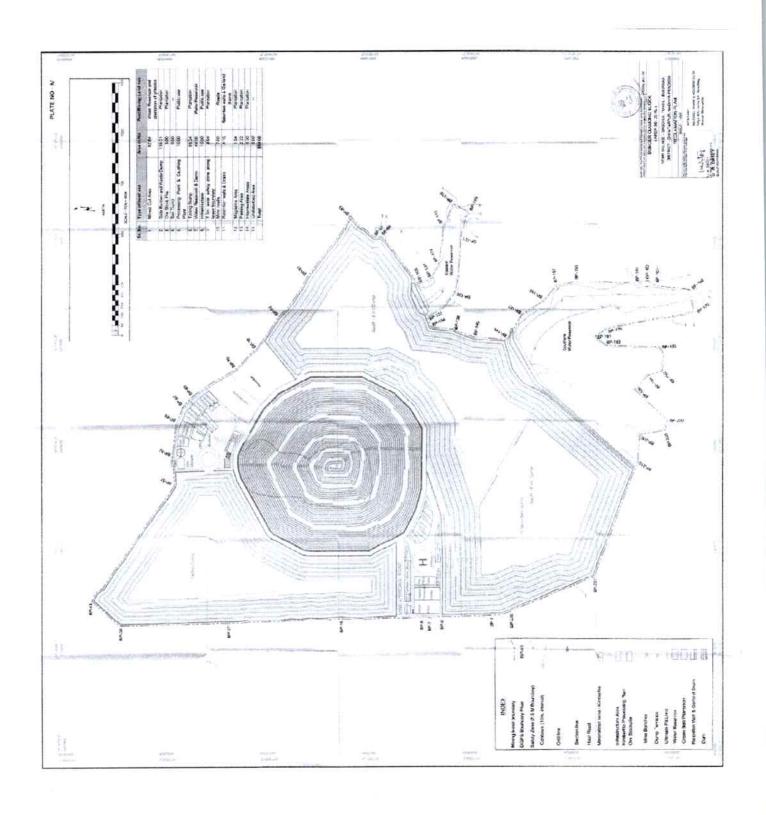
स्थानः भोपाल

भि डाडाय। (संजय मोहरीर) पदेन सचिव

म.प्र. शास्त्रन, वृत्त विभाग (संजाय नोहर्शर) पटेन सचिव, वन किशम

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या प्रदेश सिंव, वन निभाग (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा) मध्यप्रदेश शासन





कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल दूरभाष : 0755-2674318, 2674337, फैक्स : 0755-2766315 E-mail : pccfwl@mpforest.org

क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि / रियो टिंटो / माईन / 13-3 / 13 68

भोपाल, दिनांक 11-2-2016

प्रति,

श्री सिद्धार्थ जैन, चीफ आपरेटिंग आफिसर, बण्डर प्रोजेक्ट, मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, ब्लाक–1, कार्पोरेट विंग, पांचवीं मंजिल, डी.बी. मॉल, अरेरा हिल्स, अपोजिट जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल

विषय:— मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड छतरपुर द्वारा छतरपुर वृत्त अंतर्गत वनमण्डल (सा.) छतरपुर के परिक्षेत्र बकस्वाहा संरक्षित वन खंड जरा के कक्ष क्रमांक पी—279, 280, 281, 283, 284, 285, 286 एवं पी—288 रकबा 870.975 हेक्टेयर एवं परिक्षेत्र सागोरिया के संरक्षित वन खंड पी—301, 302 रकबा 100.62 हेक्टेयर कुल रकबा 971.595 हेक्टेयर वन भूमि में हीरा खनिज उत्खनन कार्य की अनुमित हेतु प्रेषित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की वन्यप्राणी स्वीकृति के संबंध में ।

संदर्भ:— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F. No. 8-22/2015-FC दिनांक 28.12.2015

- 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8543 दिनांक 15.12.2015
- 3. आपका पत्र दिनांक 09.02.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक—1 से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छतरपुर वृत्त अंतर्गत वनमण्डल (सा.) छतरपुर के परिक्षेत्र बकरवाहा संरक्षित वन खंड जरा के कक्ष क्रमांक पी—279, 280, 281, 283, 284, 285, 286 एवं पी—288 रकबा 870.975 हेक्टेयर एवं परिक्षेत्र सागोरिया के संरक्षित वन खंड पी—301, 302 रकबा 100.62 हेक्टेयर कुल रकबा 971.595 हेक्टेयर वन भूमि में हीरा खनिज उत्खनन कार्य की अनुमति हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक—1 के पालन में आपके द्वारा 06 वर्ष की अवधि हेतु रूपये 21.50 करोड़ की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी।

उक्त योजना में आवश्यक सुधार एवं संशोधन करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8543 दिनांक 15.12.2015 से निर्देश जारी किये गये थे। आपके द्वारा प्रेषित संशोधित योजना पर दिनांक 08.02.2016 को इस कार्यालय में चर्चा की गई, जिसके उपरांत संदर्भित पत्र क्रमांक 3 से

149

आपके द्वारा रूपये 30.80 करोड़ की 06 वर्ष की अवधि की संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रेषित की गई है, जिसका अनुमोदन किया जाता है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से उक्त परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उत्खनन कार्य करने के पूर्व अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में उल्लेखित कार्यों हेतु राशि वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर वनमण्डल के कार्यालय में जमा कराकर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(रवि श्रीवास्तव)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि / रियो टिंटो / माईन / 13-3 / 1369 भोपाल, दिनांक 11-2-2016 प्रतिलिपि :-

 उप वन महानिरीक्षक, (वन संरक्षण डिविजन–FCA) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्न संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, रविशंकर नगर लिंक क्रमांक-2 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

re

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि / रियो टिंटो / माईन / 13-3 / /370 भोपाल, दिनांक 1/- 2- 20/6 प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर, म.प्र.।
- जिलाध्यक्ष, (खनिज शाखा) जिला छतरपुर, म.प्र. ।
- क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना म.प्र.।
- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल छतरपुर।

की ओर अनुमोदित संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

R

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.



मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लम भवन, भोपाल

क्रमांक-। ५१ / 2308 / 2020 / 10-2 प्रति भोपाल, दिनांक 2-४ .01.2021

प्रोजेक्ट हेड बंडर डायमंड ब्लॉक एस्सल माइनिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (EMIL) आदित्य बिरला सेंटर, "ए विंग", प्रथम तल एस.के. अहिरे मार्ग, वर्ली मुंबई–400030

विषय:-Applicability of Wildlife Clearance in case of Bunder Diamond Block. संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक EMIL/HO/Bunder/2020/70 दिनांक 16 दिसम्बर, 2020.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति संरक्षित क्षेत्र, वफर क्षेत्र एवं ईको सेंसिटिव जोन से वाहर होने के कारण राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी से वन्यप्राणी अनुमति की आवश्कता नहीं है।

2/ प्रस्तावित क्षेत्र वन्यप्राणी कॉरीडोर का हिस्सा है। अतः इस क्षेत्र में वन्यप्राणी संरक्षण उपाय प्रस्तावित किया जावेगा, जिसके लिए वन्यप्राणी संरक्षण योजना एवं उसका वित्त पोषण EMIL को करना होगा।

र्घ २ 27-1-20-1 (अतुल कुमार मिश्रा) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक- 1 43 / 2308 / 2020 / 10-2 भोपाल, दिनांक 2.8.01.2021 प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश की ओर उनके पत्र क्रमांक 271 दिनांक 11.01.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



Annexure 2 - Tiger corridors in Country Press Information Bureau Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change 02 DEC 2019 4:11PM by PIB Delhi

The National Tiger Conservation Authority in collaboration with the Wildlife Institute of India has published a document titled "Connecting Tiger Populations for Long-term Conservation", which has mapped out 32 major corridors across the country, management interventions for which are operationalised through a Tiger Conservation Plan, mandated under section 38V of the Wildlife (Protection) Act, 1972. The list of macro/landscape level tiger corridors are as under:

SI. No.	Landscape	Corridor	States/ Country	
		Rajaji-Corbett	Uttarakhand	
1.	Shivalik Hills & Gangetic Plains	(ii) Corbett-Dudhwa	Uttarakhand, Uttar Pradesh, Nepal	
	Gangette Flams	(iii) Dudhwa-Kishanpur-Katerniaghat	Uttar Pradesh, Nepal	
		(i) Ranthambhore-Kuno-Madhav	Madhya Pradesh, Rajasthan	
		(ii) Bandhavgarh-Achanakmar	Madhya Pradesh, Chhattisgarh	
		(iii) Bandhavgarh-Sanjay Dubri-Guru Ghasidas	Madhya Pradesh	
		(iv) Guru Ghasidas-Palamau-Lawalong	Chhattisgarh & Jharkhand	
		(v) Kanha-Achanakmar	Madhya Pradesh, Chhattisgarh	
2.	Central India & Eastern	(vi) Kanha-Pench	Madhya Pradesh, Maharashtra	
۷.	Ghats	(vii) Pench-Satpura-Melghat	Madhya Pradesh, Maharashtra	
		(viii) Kanha-Navegaon Nagzira-Tadoba- Indravati	Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh	
		(ix) Indravati-Udanti Sitanadi-Sunabeda	Chhattisgarh, Odisha	
		(x) Similipal-Satkosia	Odisha	
		(xi) Nagarjunasagar-Sri Venkateshwara National Park	Andhra Pradesh	
		(i) Sahyadri-Radhanagari-Goa	Maharashtra, Goa	
		(ii) Dandeli Anshi-Shravathi Valley	Karnataka	
		(iii) Kudremukh-Bhadra	Karnataka	
		(iv) Nagarahole-Pusphagiri-Talakavery	Karnataka	
3.	Western Ghats	(v) Nagarahole-Bandipur-Mudumalai- Wayanad	Karnataka, Kerala, Tamil Nadu	
		(vi) Nagarahole-Mudumalai-Wayanad	Karnataka, Kerala, Tamil Nadu	
		(vii) Parambikulam-Eranikulam-Indira Gandhi	Kerala, Tamil Nadu	
		(viii) Kalakad Mundanthurai-Periyar	Kerala, Tamil Nadu	
8		(i) Kaziranga-Itanagar WLS	Assam, Arunachal Pradesh	
4.	North East	(ii) Kaziranga-Karbi Anglong	Assam	

52

(iii) Kaziranga-Nameri	Assam
(iv) Kaziranga-Orang	Assam
(v) Kaziranga-Papum Pane	Assam
(vi) Manas-Buxa	Assam, West Bengal, Bhutan
(vii) Pakke-Nameri-Sonai Rupai-Manas	Arunachal Pradesh, Assam
(viii) Dibru Saikhowa-D'Ering-Mehaong	Assam, Arunachal Pradesh
(ix) Kamlang-Kane-Tale Valley	Arunachal Pradesh
(x) Buxa-Jaldapara	West Bengal

. •





EMIL/Bunder/HO/2021/14

9 July 2021

The APCCF (Land Management) & Nodal Officer Forest Department, Government of Madhya Pradesh Satpuda Bhawan Bhopal, Madhya Pradesh

Subject: Proposal for diversion of 382.131 Ha forest land for Bunder Diamond Project in favour of M/s Essel Mining & Industries Limited District, Chhatarpur State of MP (Online Proposal No FP/MP/MIN/45288/2020)-regarding.

Reference:

- 1. Your letter no F-1/622/2021/10-11/2155 dated 2 July 2021
- Letter from MoEF&CC, New Delhi bearing letter no FC-8-04/2021-DC dated 1 July 2021

Dear Sir,

With reference to the above stated letters dated 1st & 2nd July 2021, seeking response on the EDS queries sought by MoEF&CC, New Delhi, we are herewith stating the response on the requested points below,

Point 1: Part II of the Forest diversion proposal contains details of the no of trees enumerated but the details of the actual tree felling required for the project is not provided. In this regard, it is requested to provide the complete details of actual number of trees to be felled against the figure submitted and type of mining.

Response:

- The number of trees enumerated by the state forest department within the applied forest diversion area of 382.131 Ha is 215,875 trees. It is pertinent to mention that 179,839 trees (~83.3% of total trees) are with girth size of 0 60 cm and balance 36,036 trees are with girth size more than 60 cm.
- The mine plan for the project is approved by the Indian Bureau of Mines, which provides mining
 to be undertaken in phases ensuring optimal utilization of land, therefore the tree felling will be
 phased over a period of 10 -12 years.
- The Project Proponent while undertaking mining will ensure optimal utilization of land thereby minimizing the trees felling. No tree felling will be required in the 7.5m wide safety zone along lease boundary, while tree felling will be optimised in others also. It is envisaged that about 15000 16000 trees will not come under felling during the operation of the project. Thus the total trees under impact will be less than 2 lacs. It is pertinent to mention that the Project Proponent shall be paying NPV upfront to offset the immediate loss to the ecosystem as per Hon Supreme Court directives although the tree felling is phased over the years.

Essel Mining & Industries Ltd.

Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.

T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com
W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com
Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.
Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728





- The Project Proponent as part of Compensatory Afforestation shall be planting 383,000 trees in the Compensatory Afforestation land. The plantation of 383,000 trees will be undertaken much ahead of start of mining operations and both the CA and NPV payments are done before actual start of mining.
- Additionally 425,000 trees will be planted within the lease area as part of reclamation and rehabilitation as per approved Mine plan over the life of the project.
- On 7th June 2021, the Chief Minister's Office announced multi-fold plantation to negate the impact
 by tree cutting due to developmental projects in the State. The announcement mentions that in
 Chhatarpur district, estimated 2 lakh trees will be cut for the developmental project but 10 lakh trees
 will be planted in the district. The announcement reiterated the Government's commitment to use
 Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) funds for
 additional plantation.

Point 2: Detailed note on methodology adopted on Diamond Mining

- The Project Proponent will undertake mining by adopting mechanized Opencast Method using shovel dumper combination. The unit operation for mining are site preparation, drilling, blasting, excavation, loading and transport of ore and waste. The major equipment used in mining will be drilling machines, shovels, dump trucks dozers etc.
- The mine will be designed systematically by opening up benches for excavation of ore and waste.
 The ore mined will be transported to wet mineral processing plant while the waste will be stacked in the waste dumps within the lease area.
- The ore transported to the mineral processing plant will be crushed, screened and processed for recovery of rough diamonds. The tailings generated after recovery of diamonds will be dry disposed and stacked separately in designed tailings dumps within the lease area.
- Progressive and final reclamation of mine will be undertaken as per approved mine plan and the lease will be handed over back to the forest department on mine closure.
- The mining operation will be undertaken as per the Approved mine plan and international best practice in mining operation.

Our responses may be suitably incorporated in your consolidated response to the MoEF&CC in this regard. We look forward for your earliest response on the matter to propel the project forward.

Thanking you

For Essel Mining & Industries Limited

Krishan Kant Sinha General Manager

Essel Mining & Industries Ltd.

Aditya Birla Center, 'A' Wing, 1st Floor, S.K.Ahire Marg, Worli, Mumbai 400030, India.

T: +9122 6652 5000/2499 5000|F:+9122 5562 5831/2499 5831|E: emil.corporate@adityabirla.com

W: www.adityabirla.com/www.esselmining.com

Registered Office: Industry House, 18th floor, 10, Camac Street, Kolkata 700017, India.

Corporate ID No.: U51109WB1950PLCO18728



Mining Plan for Bunder Diamond Block

Village Sagoria, Tehsil Buxwaha, District Chhatarpur, Madhya Pradesh Project Area: 364 Ha; Peak Production Capacity: 5 MTPA (ROM)



Abandoned Pits as Water Reservoirs

It is unlikely that Atri pit will be used as a water reservoir until exploration of deeper Kimberlites is completed and the viability of working the deposit at depth is investigated. If mining below the open pit in an underground mining operation is deemed viable and is approved by authorities, the Atri pit would be kept dry to reduce the risk of inundation of a potential underground operation.

Once open pit and any underground mining is complete, the Atri pit will be recontoured at surface to create a pit lake which could potentially act as a water reservoir, if the Atri pit is converted to a water reservoir.

The proposed lease being surrounded by forest area, the water from reservoir may only be used by the forest department or with their consent.

Programme for Afforestation

As stated earlier, during the first five years, plantation can be carried out over several planned green belts in the mining lease area: namely along lease boundary (7.5m), around processing plant, around infrastructure area, around magazine, etc. The total area to be planted during first five years will be approximately 12.73 ha within which an estimated 25,460 trees can be planted. During the conceptual period, plantation will be carried out over 224.5 Ha within which, about 4, 00,000 trees will be planted. Details of the proposed plantation program is given in **Table 8.8**.

Table 8.8: Proposed Green belt Development/ Plantation Programme

Year	Dumps		Worked out Benches		Backfilled area		Green Belt*		Total	
	Area Ha	Trees	Area Ha	Trees	Area Ha	Trees	Area Ha	Trees	Area Ha	Trees
1	0	0	0	0	0	0	2.88	5,760	2.88	5,760
2	0.27	540	0	0	0	0	2.80	5,600	3.07	6,140
3	0.23	460	0	0	0	0	2.40	4,800	2.63	5,260
4	0.95	1,900	0	0	0	0	0	0	0.95	1,900
5	3.20	6400	0	0	0	0	0	0	3.20	6,400
Sub	4.65	9,300	0	0	0	0	8.08	16,160	12.73	25,460
6 to life	200.0	4,00,000	24.5#	-	0	0	0	0	224.5	4,00,000
Total	204.65	4,09,300	24.5		0	0	8.08	16,160	237.23	4,25,460

* Green belt includes plantation in 7.5 m safety bartier zone, plantation around infrastructure area, around Processing Plant and around Magazine area.



	-
8	(20)

Total Tonnage	41561775			12137536			118756. 179
100-110	16861	0.842	122	•			
110 - 120	98976	0.842	122	•			
120 - 130	186655	0.813	122	-		-	
130 - 140	285160	0.812	122				1
140 - 150	417229	0.855	122		1.		
150 - 160	572212	0.847	122		-	-	10
160 - 170	727412	0.854	122				35
170 - 180	865332	0.885	122		(e)		93
180 - 190	937181	0.879	122	72 7.22			227
190 - 200	997969	0.834	122				389
200 - 210	1052728	0.818	122		-		589
210 -220	1096215	0.804	121		7 - 110		810
220 -230	1166269	0.817	121	3782	0.13	122	1023
230 - 240	1227659	0.814	121	15037	0.13	122	1281
240 - 250	1303005	0.784	121	38890	0.13	122	1520
250 - 260	1355448	0.778	121	64653	0.13	122	1813
260 - 270	1413667	0.76	121	122391	0.13	122	2078
270 - 280	1448249	0.777	121	180114	0.13	122	2371
280 - 290	1535923	0.741	121	250287	0.13	122	2639
290 - 300	1596146	0.751	121	318026	0.13	122	2991
300 - 310	1650933	0.743	121	379000	0.13	122	3355
310 - 320	1701762	0.744	121	463098	0.13	122	3741

An open pit mine with a projected diameter of 920 m and a depth of 345 m, with overall slope angles of 38° - 40° would contain 41.56 million tonne of ore in the south domain and 12.14 million tonnes in the north domain. The average incidence of diamonds of the ore will be 0.78 carat of diamond per tonne of ore reserves in the south and 0.13 carat/t in the north. The estimated recovered Diamond from 53.70 million tonne ore material will be approximately 34.20 million carats.

The confidence levels in the tonnage and incidence of diamonds estimations are sufficient to classify the Resources as economically mineable reserves under the UNFC classification system.

5.1 United Nations Framework Classification (UNFC)

5.1.1 Overview

The UNFC is a universally applicable scheme for classifying / evaluating mineral reserves/resources. The classification consists of three dimensional axial systems which include geological assessment, feasibility assessment and economic viability, expressed as a three digit code based system. The economic viability of project presents the first digit, the feasibility axis the second digit and the geology axis the third digit. Three main category are used to describe the economic viability, three to describe feasibility and four to describe the level of geological knowledge.

E:\10 BLOCKS GR REPORT\BUNDER\GR Bunder.Docx

5.1.4.3 Geophysical survey:

Ground geophysical surveys and downhole geophysical surveys have been conducted over the Bunder mine area. A total of 1095 line km of ground magnetic surveys, 7.2 line km of orientation Neno TEM surveys were completed on 8 grids within the kimberlite anomalous catchments, which identified a number of magnetic anomalies in the project area which include the Arti orebody. Down hole Gamma, resistivity, seismic and acoustic televiewer surveys were subsequently conducted on selected drill holes over the Atri Resources.

5.2 Reserves Summary

Total reserves up to depth of 345 / 350 m (100 m RL) is 53.70 Mt as under:

South Atri 41.56 Mt @ 0.78 ct / t

North Atri 12.14 Mt @ 0.13 ct / t

These are classified as under:

Proved – upto 200 mRL – 36.46 Mt UNFC Classification 111

Probable from 200 mRL to 100 mRL -17.24 Mt. UNFC Classification 122

*UNFC Classification of estimated reserves is given in Annexure 8.

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

RTEI has explored its Bunder PL area with maximum speed, safety and efficiency in a technical competent manner. As a result of these diligent efforts it has been able to delineate a definitive area that is prospective for economically minable diamondiferous kimberlites.

The Bunder kimberlite are being evaluated for their diamond potential based on their results from the samples processed in the Bunder DMC Plant.

Additional work is required to obtain more confidence in the reserves below 200 mRL and to increase the reserve.